प्रेस प्रकाशनी PRESS RELEASE

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, एस.बी.एस.मार्ग, मुंबई-400001
Department of Communication, Central Office, S.B.S.Marg, Mumbai-400001
फोन/Phone: 022- 22660502

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi
Website : www.rbi.org.in
ई-मेल/email: helpdoc@rbi.org.in

4 जून 2021

मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2021-22
मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प
2-4 जून 2021

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने आज (4 जून 2021) अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टिआर्थिक परिस्थिति का आकलन करने के आधार पर यह निर्णय लिया है कि :

- चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ़) के तहत नीतिगत रेपो दर को 4.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा जाए।

परिणामस्वरूप, एलएएफ़ के तहत रिवर्स रेपो दर बिना किसी परिवर्तन के 3.35 प्रतिशत पर और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) दर एवं बैंक दर 4.25 प्रतिशत पर बनी हुई हैं।

- यह सुनिश्चित करते हुए कि मुद्रास्फीति भविष्य में लक्ष्य के भीतर बनी रहे, एमपीसी ने टिकाऊ आधार पर संवृद्धि को बनाए रखने एवं अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से जब तक आवश्यक हो निभावकारी रुख बनाए रखने का भी निर्णय लिया।

ये निर्णय संवृद्धि को सहारा प्रदान करते हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति को +/- 2 प्रतिशत के दायरे में रखते हुए 4 प्रतिशत का मध्यावधि लक्ष्य हासिल करने के अनुरूप है।

इस निर्णय के पीछे की मुख्य सोच नीचे दिए गए विवरण में व्यक्त की गई हैं।

आकलन

वैश्विक अर्थव्यवस्था

2. अप्रैल में एमपीसी की बैठक के बाद से, वैश्विक आर्थिक सुधार गति प्राप्त कर रहा है, जो मुख्य रूप से प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) से प्रेरित और बड़े पैमाने पर टीकाकरण कार्यक्रमों और प्रोत्साहन पैकेजों द्वारा संचालित है। वायरस के संक्रामक उत्परिवर्ती और टीकाकरण में अपेक्षाकृत धीमी प्रगति के कारण संक्रमण की नई लहरों से नकारात्मक जोखिम के कारण प्रमुख उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में गतिविधि असमान बनी हुई है। विश्व वाणिज्य व्यापार में सुधार जारी है क्योंकि बाहरी मांग फिर से शुरू हो गई है, हालांकि उच्च माल ढुलाई दरें और कंटेनर अव्यवस्थाएं बाधाओं के रूप में उभर रही हैं। अधिकांश एई में सीपीआई मुद्रास्फीति मजबूत हो रही है, जो रुकी हुई मांग में सुधार होने, उच्च इनपुट कीमतों और प्रतिकूल आधार प्रभावों से प्रेरित है। प्रमुख ईएमई में मुद्रास्फीति हाल के महीनों में आम तौर पर आधिकारिक लक्ष्यों के करीब या उससे अधिक रही है, जो वैश्विक खाद्य और पण्य वस्तुओं की कीमतों में निरंतर वृद्धि के कारण बढ़ी है। वैश्विक वित्तीय स्थिति सौम्य बनी हुई है।

घरेलू अर्थव्यवस्था

3. आर्थिक अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ते हुए, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा 31 मई 2021 को जारी राष्ट्रीय आय के अनंतिम अनुमान में चौथी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 1.6 प्रतिशत वर्ष-दर-वर्ष (वर्ष-दर-वर्ष) के साथ 2020-21 के लिए भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) को 7.3 प्रतिशत के संकुचन पर रखा है। 1 जून को, भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने सामान्य दक्षिण-पश्चिम मानसून की भविष्यवाणी की है, जिसमें दीर्घावधि औसत (एलपीए) के 101 प्रतिशत वर्षा होने की संभावना जताई गई है। यह कृषि के लिए शुभ संकेत है। हालांकि, ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण में वृद्धि के साथ, ग्रामीण मांग के संकेतक – ट्रैक्टर बिक्री और दोपहिया बिक्री – ने अप्रैल के दौरान क्रमिक गिरावट दर्ज की।

4. मार्च 2021 में औद्योगिक उत्पादन में व्यापक सुधार दर्ज किया गया। खनन और बिजली उत्पादन मार्च 2019 (महामारी से पहले) के स्तर को पार कर गया, लेकिन विनिर्माण में तेजी नहीं आई। कमजोर आधार के कारण अप्रैल 2021 में कोर उद्योगों के उत्पादन में वर्ष-दर-वर्ष दो अंकों की वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि अप्रैल 2021 के दौरान जीएसटी संग्रह अपने उच्चतम स्तर पर था, मई में मॉडरेशन के संकेत हैं जैसा कि न्यून ई-वे बिल उत्पादन में परिलक्षित होता है। अन्य उच्च आवृत्ति संकेतक - बिजली उत्पादन; रेलवे माल यातायात; बंदरगाह कार्गो; स्टील की खपत; सीमेंट उत्पादन; और टोल संग्रह – में अप्रैल-मई 2021 के दौरान क्रमिक मॉडरेशन दर्ज किया गया, जो विशिष्ट गतिविधियों के लिए छूट के साथ राज्यों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों और स्थानीयकृत लॉकडाउन के प्रभाव को दर्शाता है। उत्पादन और नए आदेशों में कमी के कारण अप्रैल में 55.5 से 50.8 तक मोडरेट होने के बावजूद विनिर्माण क्रय प्रबंधन सूचकांक (पीएमआई) मई में बढ़ी हुई रही। सेवा पीएमआई, जो अप्रैल में 54.0 था, सात महीनों के निरंतर बढ़ोत्तरी के बाद मई में संकुचित (46.4) हो गया।

5. मुख्य रूप से अनुकूल आधार प्रभावों पर हेडलाइन मुद्रास्फीति मार्च में 5.5 प्रतिशत से कम होकर अप्रैल में 4.3 प्रतिशत दर्ज की गई। खाद्य मुद्रास्फीति अप्रैल में गिरकर 2.7 प्रतिशत पर आ गई, जो मार्च में 5.2 प्रतिशत थी, अनाज, सब्जियों और चीनी की कीमतों में वर्ष-दर-वर्ष गिरावट जारी रही। जबकि ईंधन मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई, कोर (खाद्य और ईंधन को छोड़कर) मुद्रास्फीति मुख्य रूप से आधार प्रभावों के कारण, आवास और स्वास्थ्य को छोड़कर अधिकांश उप-समूहों में अप्रैल में मंद हुई। परिवहन और संचार में मुद्रास्फीति दोहरे अंकों में रही।

6. अप्रैल और मई 2021 में प्रणालीगत चलनिधि बड़े अधिशेष में रही, जिसमें चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत औसत दैनिक निवल अवशोषण ₹5.2 लाख करोड़ था। आरक्षित मुद्रा (नकदी आरक्षित अनुपात में बदलाव के पहले दौर के प्रभाव के लिए समायोजित) में 28 मई 2021 को मुद्रा की मांग के कारण 12.4 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) का विस्तार हुआ। 21 मई 2021 को मुद्रा आपूर्ति (एम3) और बैंक ऋण में क्रमशः 9.9 प्रतिशत और 6.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि एक वर्ष पहले यह क्रमशः 11.7 प्रतिशत और 6.2 प्रतिशत थी। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2021-22 में (28 मई तक) 21.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़कर 598.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।

संभावनाएं

7. आगे बढ़ते हुए, मुद्रास्फीति प्रक्षेपवक्र के ऊपर और नीचे की ओर आने वाली अनिश्चितताओं से आकार लेने की संभावना है। अंतरराष्ट्रीय पण्यों की कीमतों में वृद्धि, विशेष रूप से कच्चा तेल , रसद लागत के साथ, मुद्रास्फीति की संभावनाओं के लिए उल्टा जोखिम पैदा करती है। केंद्र और राज्यों द्वारा लगाए गए उत्पाद शुल्क, उपकर और करों को पेट्रोल और डीजल की कीमतों से उत्पन्न होने वाले इनपुट लागत दबावों को नियंत्रित करने के लिए समन्वित तरीके से समायोजित करने की आवश्यकता है। एक सामान्य दक्षिण-पश्चिम मानसून के साथ आरामदायक बफर स्टॉक से अनाज की कीमतों के दबाव को नियंत्रण में रखने में मदद मिलेगी। हाल ही में आपूर्ति पक्ष के हस्तक्षेप से दलहन बाजार में तंगी को कम करने की उम्मीद है। दालों और खाद्य तेल की कीमतों पर दबाव कम करने के लिए आपूर्ति पक्ष के और उपायों की जरूरत है। घटते संक्रमण के साथ, राज्यों में प्रतिबंध और स्थानीयकृत लॉकडाउन धीरे-धीरे कम हो सकते हैं और लागत दबाव को कम करते हुए आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान को कम कर सकते हैं। कमजोर मांग की स्थिति भी पास-थ्रू कोर मुद्रास्फीति को प्रभावित कर सकती है। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, व्यापक रूप से संतुलित जोखिमों के साथ, सीपीआई मुद्रास्फीति 2021-22 के दौरान 5.1 प्रतिशत: पहली तिमाही में 5.2 प्रतिशत; दूसरी तिमाही में 5.4 प्रतिशत; तीसरी तिमाही में 4.7 प्रतिशत; और चौथी तिमाही:2021-22 में 5.3 प्रतिशत अनुमानित है (चार्ट 1)।

8. विकास की संभावनाओं की बात करें तो, ग्रामीण मांग मजबूत बनी हुई है और अपेक्षित सामान्य मानसून आगे चलकर अपनी उछाल को बनाए रखने के लिए सही है। हालाँकि, ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 संक्रमणों का बढ़ता प्रसार नकारात्मक जोखिम पैदा करता है। दूसरी लहर से शहरी मांग में कमी आई है, लेकिन एक उपयुक्त कार्य वातावरण के लिए व्यवसायों द्वारा नए कोविड-संगत व्यावसायिक मॉडल को अपनाने से आर्थिक गतिविधियों पर असर पड़ सकता है, विशेष रूप से विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में जो गहन संपर्क वाले नहीं हैं। दूसरी ओर, मजबूत वैश्विक सुधार को निर्यात क्षेत्र का समर्थन करना चाहिए। घरेलू मौद्रिक और वित्तीय स्थितियां आर्थिक गतिविधियों के लिए अत्यधिक अनुकूल और सहायक बनी हुई हैं। इसके अलावा, आने वाले महीनों में टीकाकरण प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है और इससे आर्थिक गतिविधियों को जल्दी से सामान्य करने में मदद मिलेगी। इन कारकों को ध्यान में रखते हुए, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि अब 2021-22 में 9.5 प्रतिशत होने का अनुमान है, जिसमें पहली तिमाही में 18.5 प्रतिशत; दूसरी तिमाही में 7.9 प्रतिशत; तीसरी तिमाही में 7.2 प्रतिशत; और चौथी तिमाही: 2021-22 में 6.6 प्रतिशत शामिल है (चार्ट 2)।

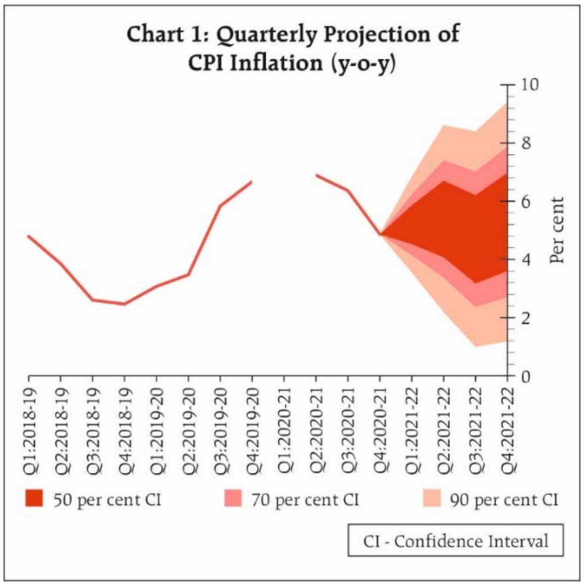

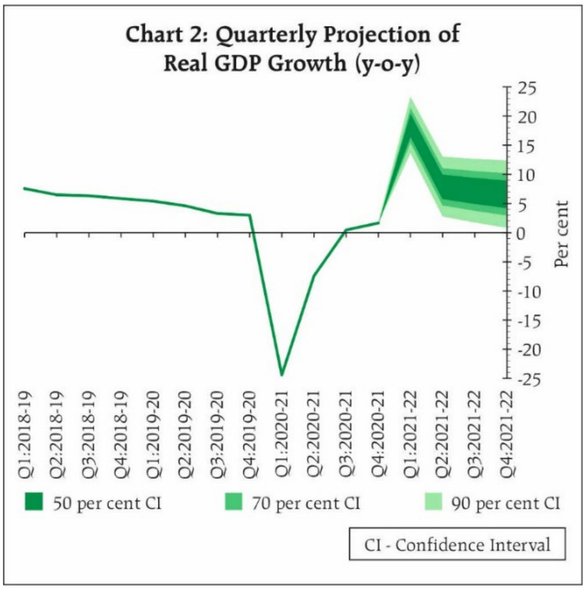

9. एमपीसी नोट करता है कि कोविड-19 की दूसरी लहर ने निकट अवधि की संभावनाओं को बदल दिया है, जिससे तत्काल नीतिगत हस्तक्षेप, सक्रिय निगरानी और समय पर उपाय करने की आवश्यकता है ताकि आपूर्ति श्रृंखला की बाधाओं के उभरने और खुदरा मार्जिन के निर्माण को रोका जा सके। टीकाकरण अभियान की तेज गति और शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे में तेजी से सुधार जीवन और आजीविका को संरक्षित करने और संक्रमण की नई लहरों में पुनरुत्थान को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। इस समय, सभी ओर से नीतिगत समर्थन - वित्तीय, मौद्रिक और क्षेत्रीय - सुधार को बढ़ावा देने और सामान्य स्थिति में वापसी में तेजी लाने की आवश्यकता है। तदनुसार, एमपीसी ने मौजूदा रेपो दर को 4 प्रतिशत पर बनाए रखने और यह सुनिश्चित करते हुए कि मुद्रास्फीति भविष्य में लक्ष्य के भीतर बनी रहे, एमपीसी ने टिकाऊ आधार पर संवृद्धि को बनाए रखने एवं अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से जब तक आवश्यक हो निभावकारी रुख बनाए रखने का निर्णय लिया।

10. एमपीसी के सभी सदस्य – डॉ. शंशाक भिडे, डॉ. आशिमा गोयल, प्रो. जयंत आर. वर्मा, डॉ. मृदुल के. सागर, डॉ. माइकल देवव्रत पात्र और श्री शक्तिकान्त दास – ने नीति रेपो दर को 4.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने के लिए सर्वसम्मति से मतदान किया। इसके अलावा, एमपीसी के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से यह सुनिश्चित करते हुए कि मुद्रास्फीति भविष्य में लक्ष्य के भीतर बनी रहे, एमपीसी ने टिकाऊ आधार पर संवृद्धि को बनाए रखने एवं अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से जब तक आवश्यक हो निभावकारी रुख बनाए रखने के लिए मतदान किया।

11. एमपीसी की बैठक का कार्यवृत्त 18 जून 2021 को प्रकाशित किया जाएगा।

12. एमपीसी की अगली बैठक 4 से 6 अगस्त 2021 के दौरान निर्धारित है।

(योगेश दयाल)
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/318